भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1626
दिनांक 2 मार्च, 2020

पीएमयूवाई के लाभार्थी

1626. कुमारी शोभा कारान्दलाजेः
श्री पी॰सी॰ मोहनः
श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हाः
श्री बसंत कुमार पांडाः
श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पाः
श्रीमती रंजीता कोलीः
डॉ॰ आलोक कुमार सुमनः
कुमारी राम्या हरिदासः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत से अब तक प्रदान किए गए रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा सम्पूर्ण देश में पीएमयूवाई के अन्तर्गत राज्य-वार विशेषकर गोवा, ओडिशा में कालाहांडी तथा बिहार में गोपालगंज और कर्नाटक एवं राजस्थान के जिलों में कितने कनेक्शन जारी किए गए हैं;

(ख) आम उपभोक्ताओं को कितनी राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत परिवारों को एलपीजी के प्रावधान के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर कर्नाटक और गोवा में केरोसीन तेल के उपभोक्ताओं की संख्या में कुल कितनी कमी आई है;

(घ) देश में राज्य-वार विशेषकर दक्षिण गोवा और गोवा के उत्तरी गोवा जिलों और बिहार और राजस्थान के जिलों में कितने परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाने शेष हैं तथा सरकार द्वारा उक्त कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास लाभार्थियों द्वारा दूसरी बार गैस सिलेंडर भरवाने का रिकॉर्ड है तथा यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान उज्ज्वला लाभार्थियों द्वारा भरवाए गए कुल गैस सिलेंडरों की राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक में ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा सिलेंडर भरवाना सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क): प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने का लक्ष्य 7 सितंबर, 2019 को पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। पीएमयूवाई के तहत गोवा राज्य, ओडिशा में कालाहांडी, बिहार में गोपालगंज, कर्नाटक और राजस्थान में जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	**पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या**
गोवा	0.01 लाख
कर्नाटक	31.47 लाख
राजस्थान	63.81 लाख
ओडिशा (कालाहांडी जिला)	2.02 लाख
बिहार (गोपालगंज जिला)	1.74 लाख

(ख): पीएमयूवाई एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली में फरवरी माह, 2020 में दिनांक 12.02.2020 से लागू राजसहायता 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर के लिए 312.48 रुपए है।

(ग): पीडीएस मिट्टी तेल आबंटन को वैद्युत संबद्धता, एलपीजी पैठ और राज्यों/यूटीज समाप्त हो गए कोटे जैसे कारकों को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त बनाया गया है। सरकार ने कर्नाटक और गोवा राज्यों में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,56,000 और 2,112 कि.ली. और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 84,324 और 816 कि.ली. आबंटित किया है।

(घ): दिनांक 01.02.2020 की स्थिति के अनुसार, देश की एलपीजी कवरेज लगभग 97.3% है। एलपीजी कनेक्शन जारी किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को हिदायत दी गई है कि वे नए एलपीजी कनेक्शन के लिए मिलने वाले अनुरोध को तुरंत पंजीकृत करें और तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) उसे 7 कार्य दिवसों के भीतर जारी करने का प्रयास करती हैं। दिनांक 01.02.2020 की स्थिति के अनुसार, गोवा, बिहार और राजस्थान राज्यों में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

राज्य	**एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या**	**एलपीजी कवरेज**
गोवा	4.99 लाख	144%
बिहार	174.84 लाख	75.3%
राजस्थान	161.82 लाख	108.1%

(ड.) और (च): ओएमसीज ने बताया है कि 85% पीएमयूवाई लाभार्थी रीफिल लेने के लिए वापस आए हैं। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, पीएमयू उपभोक्ताओं ने देश भर में 28.90 करोड़ एलपीजी रीफिलों और कर्नाटक राज्य में 79.78 लाख रीफिलों की खपत की है। पीएमयूवाई लाभार्थियों की रीफिल खपत में वृद्धि करने के लिए ओएमसीज द्वारा उठाए गए मुख्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- रीफिल खपत को बढ़ावा देने के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों से राजसहायता से ऋण की वसूली 6 रीफिलों या 1 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए स्थगित करना।
- 14.2 कि.ग्रा. रीफिल के बदले में अपनी मांग के अनुसार 5 कि.ग्रा. रीफिल का छोटा पैकेज बदलने की सुविधा देना।
- प्रधान मंत्री एलपीजी पंचायत और मेला, एक समुदाय आधारित कार्यक्रम चलाना ताकि एलपीजी के इस्तेमाल से संबंधित किसी मुद्दे का समाधान किया जा सके।
- पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2019) के दौरान 6600 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करके अंतिम एलपीजी उपभोक्ता तक पहुंच बढ़ाना।
- भारत भर में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए बुकिंग सुविधाएं प्रदान करना।
- रीफिल खपत में वृद्धि करने के लिए क्षेत्र विशेष की कार्यनीतियां अपनाते हुए डिस्ट्रीब्यूटरों/बिक्री क्षेत्र की नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करना।

*****